

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
10.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2808 का उत्तर

तिरुतुरैपूंडी-वेलांकणि के बीच नई पटरी बिछाना

2808. श्री एम. सेल्वराज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तिरुतुरैपूंडी से वेलांकणि के बीच नई रेलवे पटरी बिछाने का कार्य गत दस वर्षों के दौरान प्रगति पर है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कार्य की गति बढ़ाने के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा होने और इस मार्ग में रेल सेवा आरंभ होने की संभावना है; और
- (घ) आज तक इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित/आबंटित की गई है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

तिरुतुरैपूंडी-वेलांकणि के बीच नई पटरी बिछाने के संबंध में दिनांक 10.07.2019 को श्री एम. सेल्वराज के अतारांकित प्रश्न सं. 2808 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): तिरुतुरैपूंडी से वेलांकणि तक नई लाइन का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। बहरहाल, तिरुचिरापल्ली-नागौर आमान परिवर्तन परियोजना के महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में दो अलग नई लाइन कार्य यथा नागापट्टिनम-वेलांकणि (10 कि.मी.) और नागापट्टिनम-तिरुतुरैपूंडी (43 कि.मी.) स्वीकृत किए गए थे।

1. नागापट्टिनम-वेलांकणि नई लाइन (10 कि.मी.) 1999-2000 के दौरान स्वीकृत की गई थी और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

2. नागापट्टिनम-तिरुतुरैपूंडी नई लाइन कार्य (43 कि.मी.) 2008-09 के दौरान 126.14 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था और जहां कहीं भूमि उपलब्ध है भूमि अधिग्रहण, मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर), विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल, जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालय के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंत में पूरा होने की स्थिति पर गणना की जाती है।

समग्र राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना बिना लागत में वृद्धि के पूरी हो जाएं, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय से पहले भी पूरी हो जाती हैं, रेलवे ने निविदा में बोनस क्लॉज के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन की अवधारणा को अपनाया है जो परियोजना के निष्पादन की गति में और वृद्धि करेगा।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

चूँकि राज्य सरकार द्वारा रेलों को अभी तक समूची निर्बाध भूमि नहीं सौंपी गई है। इसलिए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, फिलहाल कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

तथापि, मार्च 2019 तक उक्त महत्वपूर्ण आशोधनों सहित तिरुचिरापल्ली-नागौर-आमान परिवर्तन परियोजना पर 637.74 करोड़ रु. का खर्च किया गया है और 2019-20 के दौरान 40 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

\*\*\*\*\*